Vol 6 Issue 6 December 2016 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

GRT Golden Research Thoughts

ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 4.6052(UIF) Volume - 6 | Issue - 6 | December - 2016

भ्रष्टाचार, जन–आन्दोलन और मीडिया: भारतीय सन्दर्भ

डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र
अतिथि व्याख्याता , राजनीति विज्ञान विभाग ,
शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारत में भ्रष्टाचार; उसके विरूद्ध हुए जन–आन्दोलनों तथा इन आन्दोलनों में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके अन्तर्गत प्रथम भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के उदाहरण के रूप में 'सम्पूर्ण क्रान्ति' जबकि द्वितीय भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के उदाहरण के रूप में अन्ना हजारे के 'भ्रष्टाचार के विरूद्ध भारत' (इण्डिया अगेन्स्ट करप्शन) को लिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र इन आन्दोलनों के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने के साथ ही बदले–बदलते विश्व में लोकतन्त्र के चतुर्थ स्तम्भः मीडिया के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों को पर केन्द्रित है।

प्रमुख बिन्दु: प्रस्तावना, भ्रष्टाचारः अर्थ निरूपण, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन और मीडिया, मीडिया उत्तरदायित्व और चुनौतियां, निष्कर्ष।

प्रास्ताविक :

सम्प्रति विश्व में भ्रष्टाचार तथा समावेशी विकास की दिशा के विपरीत दिशा में विकास के विरूद्ध अनेक जन आन्दोलन हो रहे हैं। 'अरब बसन्त' से लेकर अमरीका में 'वॉल स्ट्रीट' पर कब्जा करने सम्बन्धी आन्दोलन और भारत में 'जनलोकपाल' से लेकर 'काले धन के विरूद्ध' चल रहे आन्दोलन इस तथ्य के साक्षी हैं कि आधुनिक समाज; वर्तमान व्यवस्था से न सिर्फ असन्तुष्ट हैं वरन् वे इसमें परिवर्तन के लिए

अपनी भूमिका को निभाने के लिए कृतसंकल्प भी हैं। वस्तुतः इन आन्दोलनों के उभार–प्रसार और व्यापीकरण में मीडिया की भी अपनी एक प्रमुख भूमिका है। वर्तमान वैश्वीकृत समाज और सूचना–प्रौद्योगिकी के युग में मीडिया वह प्रमुख कारक है जिसने न सिर्फ इन आन्दोलनों को एक आधार प्रदान किया वरन् तत्सम्बन्धित अनेक पहलुओं पर परिचर्चा के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराया। संक्षेप में, आधुनिक विकासशील देशों के समाजीकरण में मीडिया की भूमिका प्रमुख होती जा रही है जिसे लोकतन्त्र और नागरिक समाज के भविष्य की दिशा में शुभ संकेत मानना चाहिए।

भ्रष्टाचारः अर्थ निरूपण

वर्तमान समय में जिस शब्द की सर्वाधिक चर्चा हो रही है वह शब्द भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार दो शब्दों:भ्रष्ट+आचार से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'निषिद्ध नियमों के अनुरूप व्यवहार करना' (बिगोवी, 2005)। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति उन तरीकों से अपने आप को लाभ पहुंचाता है जिन्हे सभ्य समाज में व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं है तो उसे भ्रष्ट आचारशील व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समाज में हमारे समाज में भ्रष्टाचार के कई प्रकार उद्घाटित हो रहे हैं। रिश्वत लेकर कार्य करना, किसी को अनैतिक कार्य के लिए विवश करना, कार्यस्थलों पर महिला सहकर्मियों का मानसिक–यौन शोषण; उनसे दुर्व्यवहार, अल्प–वयस्क बालक–बालिकाओं का अनैतिक कार्यों के लिए बलात्–व्यापार, अपेक्षाकृत पिछड़े और निर्धन समाजों से अनैतिक कार्यों के लिए महिलाओं की खरीद–फरोख्त आदि–आदि भ्रष्टाचार के विविध रूप हैं। वास्तव में भ्रष्टाचार आज नित नए रूप धारण करता जा रहा है और यदि इसे समय पर न रोका गया तो यह हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था को अपने पाश में जकड़ सकता है।

भारत में भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन और मीडिया

किसी भी समाज में प्रायः जन आन्दोलन तब शुरू होते हैं जब जनता कुछ निश्चित बातों या वस्तुओं से सन्तुष्ट नहीं होती है। वंचित होने की भावना, ढ़ांचागत विकृति और व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा;वे प्रेरक तत्व हैं जो जन आन्दोलनों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका प्रमुखता से निभाते हैं। दूसरे, जन आन्दोलन जहां व्यवस्था के विरूद्ध अपनी असहमति और असन्तुष्टि को अभिव्यक्त करते हैं वहीं दूसरी ओर वे एक सकारात्मक विकल्प को भी प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में इस प्रकार के आन्दोलनों में जनता की बढ़ती भागीदारी और आन्दोलनों की क्षमताएं, जनता की राजनीतिक प्रक्रिया से विरक्तिता तथा निराशा एवं राजनीतिक दलों, राज्य तथा राज्य शक्ति के प्रति बढ़ते असन्तोष को दर्शाती हैं।

भारत में, लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाए जाने के बावजूद, आजादी के बाद से ही राज्य की प्रकृति, राजव्यवस्था से हो रही लोगों की मांगों को पूरा करने में राजव्यवस्था की असमर्थता, राज्य कार्यपालिका की भूमिका और व्यवहार, नौकरशाही की परम्परागत औपनिवेशिक प्रकृति तथा देश और समाज के भविष्य के लिए की जा रही आशाओं में विषमता के उदय होने के कारण देश में कई प्रकार के आन्दोलन शुरू हुए। यद्यपि ये आन्दोलन अलग–अलग विभिन्न उद्देश्यों के सन्दर्भ में परिचालित हुए तथापि इन्होने देश को शासकीय नीतियों का न सिर्फ विरोध करना सिखाया वरन् अपने अधिकारों और हितों के प्रति जागरूक भी किया।

मीडिया प्रारम्भ से ही जन आन्दोलनों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रूख प्रदर्शित करता रहा है। यद्यपि प्रारम्भ में देश में मीडिया के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन और औपनिवेशिक कालीन कुछ समाचार पत्र ही थे, तथापि अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के

द्वारा मीडिया के दोनो स्वरूपों–इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा। किन्तु 1975 में देश में लागू हुए आपातकाल ने न सिर्फ मीडिया की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया वरन् इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह आरोपित हो गये। तब से आज तक अनेक उतार–चढ़ावों के बीचमीडिया ने न सिर्फ अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा है वरन् इसने सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण वाहक के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है।

भारत में जन आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका को दो सन्दर्भों– प्रथम, 1975 के आपातकाल एवं द्वितीय, 2011 के जनलोकपाल को लेकर हुए अन्ना आन्दोलनमें देख जा सकता है। आपातकाल के दौरान जहां मीडिया को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा वहीं जनलोकपाल आन्दोलन के समय लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया की भूमिका न सिर्फ मुखर हुई वरन इसने जन–जागरूकता, सामाजिक पुनर्निर्माण और लोकतन्त्र सशक्तीकरण के कार्य को भी कुशलता से सम्पन्न किया।

राष्ट्रीय आपातकाल और मीडिया

1947 में देश की स्वतन्त्रता के बाद विचार–अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रतीक 'मीडिया' के ऊपर एक बड़ा संकट 25 जून 1975 की रात को तब आया जब 'आन्तरिक अशान्ति' के नाम पर देश में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गयी। उल्लेखनीय है कि यह घोषणा जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के आन्दोलन से उपजी परिस्थितियों के सन्दर्भ में की गयी थी। लोकतान्त्रिक भारत में इस प्रकार लागू किए गये आपातकाल ने न सिर्फ प्रेस पर सेंसरशिप आरोपित की वरन् मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए।

ध्यातव्य है कि वर्ष 1974 तक पत्रकारिता के माध्यम से शासन और सरकार की सर्वत्र आलोचना हो रही थी। देश में भ्रष्टाचार, अराजकता और कुव्यवस्था के विरोध में समाचार पत्रों में बढ़–चढ़ कर लिखा जा रहा था। गुजरात और बिहार में छात्र आन्दोलनों ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस आन्दोलन के क्रम में छात्रों ने अपने नेतृत्व हेतु जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जे.पी. ने आन्दोलन के नेतृत्व को स्वीकारते हुए सामाजिक, आार्थिक और राजनीतिक दायरे में 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का आह्वान किया ताकि देश में 'सच्चे लोकतन्त्र' की स्थापना की जा सके।जे.पी. के संसद मार्च के निर्णय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार देने के निर्णय और 25 जून 1975 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित की गई विशाल जनसभा आदि घटनाओं की अन्तिम परिणति राष्ट्रीय आपात के रूप में हुई।

आपातकालीन कार्यवाहियों का पहला शिकार प्रेस ही हुआ। 25 जून की आधी रात के बाद ही सभी बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई। प्रेस की आजादी पर रोक लगाते हुए प्रेस सेंसरशिप को लागू किया गया। प्रेस को इस प्रकार नियन्त्रित करने के निर्णय सर्वत्र विरोध हुआ। 'इण्डियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' जैसे पत्र इस विरोध के प्रतीक बने। सेमीनार, मेनस्ट्रीम और ओपिनयन जैसे पत्र–पत्रिकाओं ने सरकारी प्रतिबन्धों के विरूद्ध बंद होना उचित समझा। विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को भारत से बाहर निकाल दिया गया। आपातकाल के पूर्व की चार समाचार समितियों– यू.एन.आई., पी.टी.आई., हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय कर एक समाचार समिति का गठन किया गया ताकि इसे पूर्णतया सरकारी नियन्त्रण में रखा जा सके। दूरदर्शन और रेडियो के प्रसारणों को भी इसी प्रकार नियन्त्रित किया गया। दूरदर्शन तो इस काल में सरकारी नीतियों और सत्ता के प्रचार–प्रसार का एक सशक्त माध्यम ही बन गया। बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमरीका अब लोगों के लिए सूचनाओं का एक विश्वसनीय स्रोत बन गये।

इस सम्पूर्ण घटनाक्रम का दूसरा किन्तु आाश्चर्यजनक पहलू यह था कि मीडिया ने इन प्रतिबन्धों को सरलता से स्वीकार नहीं किया। विरोध के अपने नए तौर–तरीकों से मीडिया ने तत्कालीन समय में एक नयी भूमिका का निभाई। कई सम्पादकों ने सम्पादकीय का स्थान खाली छोड़ कर तो कुछ ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के पक्ष में महापुरूषों की उक्तियों को छाप कर सरकार का विरोध किया। लगभग 300 पत्रकारों को मीसा में बन्द किया गया। आपातकाल की पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गये थे वे भूमिगत हो गये और भूमिगत रह कर ही उन्होने समानान्तर प्रचार–तन्त्र को तैयार किया।आपातकाल के इस दौर में पत्रकार भी दो वर्गों में विभाजित हो गये। एक ओर वे पत्रकार थे जिन्होने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को पवित्र माना तथा इसके लिए कारावास की यातनाएं भोगीं। दूसरी ओर ऐसे पत्रकारों की भी कमी नहीं थी जिन्होने न सिर्फ सेंसरशिप को स्वीकार किया वरन् आपातकाल का 'अनुशासनपर्व' के रूप में स्वागत भी किया। संक्षेप में; आपातकाल के दौरान मीडिया पूरी तरह से सरकारी शिकंजे में जकड़ गया।

मीडिया पर इस प्रकार के सरकारी नियन्त्रण का एक कुप्रभाव यह हुआ कि इस समय सूचनाओं का एकतरफा आदान–प्रदान हुआ। सरकारी नीतियों–कार्यक्रमों की जानकारी जनता को मिलती रही लेकिन आपातकालीन विरोधी जनता का दृष्टिकोण को समझने के लिए सरकार के पास सूचनाओं का पर्याप्त अभाव था। 18 माह के घुटन भरे वातावरण के बाद अंततः जनवरी' 1977 में सरकार ने आम चुनाव करने का निर्णय किया। 1977 के मार्च माह में देश में आम चुनाव हुए। वास्तव में 1977 के आम चुनाव एक प्रकार से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह था। विपक्ष ने 'लोकतन्त्र बचाओ' के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निश्चित रूप से आपातकाल के विरूद्ध था जो कि इन चुनावों में, देश की स्वतन्त्रता के बाद,पहली बार हुई कांग्रेस की हार से स्पष्ट हो गया।

वास्तव में 1975–77 का अनुभव भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक सबक था कि लोकतन्त्र में कोई भी सरकार, यदि जनभावनाओं को समझने में असफल रहती है तो जनता उसे निश्चित रूप से नकार देगी। दूसरे, देश की जनता ने आपातकाल और और प्रेस सेंसरशिप के विरूद्ध मतदान करके यह भी बता दिया कि एक सभ्य समाज और लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने वालों को वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने तीसरे और अन्तिम अर्थ में इन अनुभवों की परिणति भारतीय लोकतन्त्र के आधार को सशक्त बनाने में हुई।आपातकाल का अनुभव मीडिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आया और वह यह था कि मीडिया का उद्देश्य सिर्फ सूचनाओं का पारेषण करना ही नहीं है। वास्तव में मीडिया लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ होने के साथ–साथ सामाजिक पुनर्निर्माण और जनमत की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक भी है और उसे अपनी इस भूमिका को गुरूता से निभाना होगा। मीडिया ने अपने इस उत्तरदायित्व को बखूबी समझा जिसकी चरम परिणति 2011 के जनलोकपाल को लेकर हुए अन्ना आन्दोलन में देखने को मिली।

जनलोकपाल आन्दोलन और मीडिया

भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनों में, जनलोकपाल के मुद्दे पर 2011 में, समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उल्लेखनीय है कि इस आन्दोलन के पूर्व से ही 2जी घोटाला, आदर्श सोसाईटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, मंहगाई और भ्रष्टाचार जैसे अनेक ऐसे मुद्दे थे जिन्होने आम जनता को सड़क पर आने के लिए विवश कर दिया था। अन्ना आन्दोलन ने इस प्रकार भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता को सामने आने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। अन्ना के नेतृत्व में चले इस आन्दोलन में मीडिया की प्रमुख भूमिका रही। जैसा कि बाद में स्वयं अन्ना ने स्वयं स्वीकार किया कि, ''यह मीडिया है जो मुझे राष्ट्रीय आइकॅन बनाने का उत्तरदायी है।''

वस्तुतः 1975 और 2011 के आन्दोलनों में कुछ प्रमुख मौलिक भेद थे। प्रथम, 1975 में देश के जनमानस पर स्वाधीनता संग्रामकालीन आदर्शों

की छाया अवशेष थी जबकि 2011 तक देश में एक नई पीढ़ी का उदय हो चुका था जो नारों से अधिक कार्यों और आदर्शों से अधिक यथार्थ में विश्वास रखती थी। दूसरा, आर्थिक उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 24ग7समय चलने वाले समाचार चैनल; जो कि 21वीं सदी में सूचना प्रसारण की एक सशक्त पहचान बन चुके हैं; का 1975 में सर्वथा अभाव था और तीसरे, 2011 में मीडिया के एक नए रूप– सोशल अथवा वैकल्पिक मीडिया का उदय हो चुका था जबकि जे.पी. आन्दोलन सोशल मीडिया के लाभों से वंचित था।

उल्लेखनीय है कि अन्ना आन्दोलन के दौरान मीडिया के सभी रूपों ने अपनी भूमिका का निवर्हन बखूबी किया। अन्ना आन्दोलन और उससे जुड़ी खबरों का 24ग7 समाचार चैनलों ने सीधा प्रसारण किया। समाचार पत्रों ने व्यापक बहस के लिए एक मंच प्रदान किया और देश में आन्दोलन समर्थक वातावरण तैयार किया। लेकिन इस सब के बीच जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वह था आन्दोलन के दौरान सोशल मीडिया का जमकर किया जाने वाला प्रयोग। वास्तव में यह सोशल मीडिया ही था जिसने युवाओं को इस आन्दोलन के पक्ष में संगठित किया। भारतीय इतिहास में किसी आन्दोलन के सन्दर्भ में सोशल मीडिया के संगठित प्रयोग का यह पहला उदाहरण था (पाराशर, 2012)।

वस्तुतः सम्पूर्ण घटनाक्रम को विशाल आन्दोलन में बदलने का कार्य वास्तव में सोशल मीडिया द्वारा ही किया गया। यद्यपि भारत में सोशल मीडिया का प्रसार मात्र शहरी इलाकों तक ही सीमित है तथापि इसने आन्दोलन सम्बन्धी सन्देशों को कई रूपों में अनेक लोगों तक पहुंचाया जिसके बाद प्रचलित मीडिया द्वारा इस आन्दोलन की उपेक्षा करना असम्भव था। दूसरे, टीम अन्ना द्वारा 'आम आदमी' को पूरे आन्दोलन के केन्द्र में रखने की रणनीति ने प्रचलित मीडिया कोइस मुद्दे को गम्भीरता से लेने के लिए बाध्य किया।

यह मीडिया प्रचार तन्त्र ही था जिसने प्रारम्भ में मात्र शहरी क्षेत्रों से शुरू हुए एक घटनाक्रम को राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का रूप दिया। आन्दोलन के प्रसारण के दौरान मीडिया द्वारा आन्दोलन को 'द्वितीय स्वाधीनता संग्राम' और 'अगस्त क्रान्ति' जैसे प्रतीकों से विभूषित करने की रणनीति ने जनमानस का ध्यान स्वतः ही आन्दोलन की ओर आकृष्ट किया। परिणामस्वरूप गांधी के देश में अहिंसावादी–सत्याग्रही आन्दोलन का नया दौर पुनः लौटा। वस्तुतः अन्तिम मूल्यांकन में अन्ना आन्दोलन को 'लाखों लोगों' द्वारा 'पूरे देश में' लड़े जाने वाले 'दूसरे स्वतन्त्रता आन्दोलन' के रूप में याद रखा जाएगा, यद्यपि वास्तव में यह एक लोकप्रिय, अधिकतर शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित, भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने एक कानून निर्माण की मांग को ले कर चलाया गया आन्दोलन था (मोहापात्रा, 2013)और यह सब मीडिया के प्रचार तन्त्र का ही परिणाम था।

मीडियाः उत्तरदायित्व और चुनौतियां

वर्तमान समय भारत और स्वयं मीडिया भी एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक उदारीकरण से उपजी परिस्थितियों में बड़े औद्योगिक घरानों की मीडिया के क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ी है। परिणामस्वरूप 'निवेशक जो कहे, सो सही' की तर्ज पर पत्रकारिता अब देश सेवा की जगह वृत्ति का रूप धारण कर रही है। पूंजीवादी चकाचौंध और कारपोरेट संस्कृति से अब मीडिया भी अछूता नहीं हैं फलतः बाजार/भौतिकतावादी अपकर्ष के छींटे कई बार मीडिया के दामन पर भी गिरे हैं। आधुनिक भारत की परिस्थितियों को देखते हुए मीडिया से यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने उत्तदायित्वों को समझे। जनमानस आज भी मीडिया को श्रद्धा भाव से देखता है। इस भाव को कायम रखने का उत्तरदायित्व मीडिया ही निभा सकता है। दूसरी, मीडिया के समक्ष बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने की है। समाचारों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति तथा पेड न्यूज–सर्वे मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं अतः मीडिया को अपने व्यवसायिक हितों और पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों के बीच सन्तुलन कायम करने की आवश्यकता है। अन्तिम रूप में, मीडिया के समक्ष सामाजिक पुनर्निर्माण की चुनौती है। मीडिया के योगदान के अन्तिम मूल्यांकन की वास्तविक कसौटी यही होगी कि वह सामाजिक पुनर्निर्माण के अपने दायित्व को किस सीमा तक निभा सका तथा बदले–बदलते भारत की आावश्यकतानुरूप अपने को किस प्रकार ढ़ाल सका।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसी भी लोकतन्त्र में मीडिया का अपना विशिष्ट स्थान है। लोकतन्त्र का चतुर्थ स्तम्भ होने के साथ ही मीडियाजनमत निर्माण का एक अपरिहार्य साधन और यह लोगों की स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति का प्रतीक भी है। प्रतिबन्धित और नियन्त्रित मीडिया किसी भी लोकतान्त्रिक समाज के भविष्य के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। वर्तमान संक्रमणकालीन परिस्थितियों, जहां 'सार्वजनिक जीवन की शुचिता बनाम भ्रष्टाचार' का द्वन्द्व स्पष्ट है, मीडिया का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मीडिया अपने उत्तरदायित्वों को समझे और पूंजीवादी विकृतियों से अपने का बचाते हुए सामाजिक निर्माण की दिशा में कार्य करे। इससे न सिर्फ मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी वरन् यह भारतीय लोकतन्त्र के लिए भी शुभ सिद्ध होगा।

सन्दर्भ

1.बिगोवी, बोरिस (2005): करप्शनः कॉन्सेप्ट, टाइप्स, काउज, कॉनसिक्वेन्सेज;इकॉनॉमिक रिफोर्म सर्विस,सेन्टर फॉर इन्टरनेशनल प्राइवेट इन्टरप्राइज, वॉशिंगटन.

2.मोहापात्रा, डॉ. अतानु (2013), लोकपाल एंड द रोल ऑफ मीडिया इन प्रोपिंग अप एन्टी करप्शन मूवमेन्ट इन इण्डिया, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइन्स एंड इंटरडिसिप्लनरी रिसर्च, वाल्यूम 2 (3), आई.जे.एस.एस.आई.आर.

3.रोजसा, इरजसेबेट एन0 एवं अन्य (2012): द अरब स्प्रिंगः इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजन एण्ड ऑन द मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेन्स, पॉलिसी ब्रीफ;एकेडेमिक पीस आरक्रेस्ट्रा मिडल ईस्ट, छवेण्9ध्10यअगस्त 2012.

4.नारंग, अमरजीत सिंह (2005): भारतीय शासन और राजनीति; गीतान्जली पब्लिशिंग हाऊस, नयी दिल्ली.

5.मंगलानी, डॉ0 रूपा (2015): भारतीय शासन एवं राजनीति; राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी; जयपुर.

6.पाराशर, अतीश (2012): एन एनालिसिस ऑफ न्यू मीडियाज रोल इन मास मूवमेन्ट (विद रेफरेन्स टू अन्ना हजारे'ज कैम्पेन 'इण्डिया अगेन्स्ट करप्शन'); जे मास कम्युन जर्नलिज्म (2:7).

7.नारायण, जयप्रकाश (1990): नेशन बिल्डिंग इन इण्डिया; नवचेतना प्रकाशन; बनारस

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org